

बस में बैठकर गांव पहुंचे कलेक्टर नामदेव, बच्चों संग खेला वॉलीबाल

पंगत में किया भोजन और खाट पर ही सो गए, सादगी देख जमकर हो रही तारीफ

मंडला (नप्र)। जिले के अंदरूनी गांव ‘दाढ़ी’ में जिले के मुखिया कलेक्टर रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उन्हें हल कराने पहुंचे थे। यहां उन्होंने एसपी, जिला पंचायत सीईओ संग पंगत में बैठकर भोजन किया और रात में खुले आसमान के नीचे खाट पर मछरदानी लगाकर सो गए। साहब का यह रूप देख ग्रामीण अचंभित और गदगद हो गए। आईएसएस राहुल नामदेव की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में तस्वीर कुछ बदली-बदली सी नजर आ रही है। ऐसी चैबरो में बैठकर जिले का शासन चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी अब गांव में चौपाल लगाते दिख रहे हैं। ऐसा ही नजारा प्रदेश के मंडला जिले से सामने आया। कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश खुबंशी



सहित तमाम प्रशासनिक अमला यहां रात्रि चौपाल लगाने पहुंचा था। सबसे अहम बात अधिकारी हटर बजाती लालबत्ती ऐसी गाड़ियों के बजाय बस दाढ़ी गांव से पहुंचे थे।

खुलेआसमान के नीचे खाट पर मच्छरदानी लगाकर सो गए- दरअसल एमपी के मंडला जिले में मवई के ग्राम दाढ़ी में

कलेक्टर कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश खुबंशी और ने दाढ़ी में प्रशासन आपके द्वार की कल्पना को साकार किया। उन्होंने यहां शाम को चौपाल लगाकर फर्श पर बैठकर गांव वालों से संवाद किया। उनकी समस्याएं और परेशानी सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। रात में प्रशासन की तरफ से यहां

सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने प्रोटोकॉल छोड़कर जमीन पर सादगी से भोजन किया और खुले आसमान के नीचे मच्छरदानी लगाकर रात गुजारी।

सुबह युवाओं संग वॉलीबॉल खेलते नजर आए अधिकारी- सुबह मच्छरदानी से निकलकर अधिकारी गांव में युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए। कलेक्टर-एसपी जैसे अधिकारियों को अपने बीच देख युवाओं में भारी उत्साह रहा। इसके बाद, पुरा प्रशासनिक अमला गलियों में पैदल निकल पड़ा। उन्हें देख बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा भी इस अभियान से जुड़ते चले गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान किया।

राजनीति ईमानदार होगी तभी गांधी -

लोहिया के सपने साकार होंगे: रघु ठाकुर

ग्वालियर। समाजवादी चिंतक व लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक रघु ठाकुर ने कहा है कि राजनीति जब ईमानदार होगी तब महत्वा गांधी और लोहिया के विचार साकार होंगे। जनता के पास जाकर उसका दिल जीतने और सादगी को आचरण में उतारने पर ही देश की राजनीति बदलेगी।

रघु ठाकुर ग्वालियर में लोसपा के दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। बघेल छात्रावास में यह शिविर दो दिन के इस शिविर में पार्टी के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र में पार्टी के संगठन निर्माण पर चर्चा हुई। दूसरे सत्र में रघु ठाकुर के वक्तव्य का विषय था ‘दुनिया की समस्याओं का हल गांधी एवं लोहिया के विचारों में है। रघु ठाकुर ने कहा कि देशवासियों के मस्तिष्क में चेतना पैदा करने के लिए एक ऐसे सांस्कृतिक अभियान की जरूरत है जो लोगों को गुलाम मानसिकता को समाप्त

करने, जातिवाद खत्म करने और हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी होने का मतलब समय पर विरोध करना है। बिना तकलीफ सहें परिवर्तन का सपना देखना खुद को धोखा देना है।

रघु ठाकुर ने नीट पेपर लोक होने के मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि गुनाहगार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बजाय ‘मन की बात’ में बिहार के सत्तु और आम की बात की जा रही है। जबकि पेपर लोक प्रकरण में सत्रह बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और परीक्षा में पास होने वाले और न होने वाले सबके हिस्से में बेरोजगारी आई है।

काकरोच जनता पार्टी की तुलना जसा आंदोलन से करते हुए रघु ठाकुर ने कहा तब अजब टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले और जनलोकपाल के मुद्दे पर वह आंदोलन हुआ था उसका हासिल क्या रहा।

संक्षिप्त समाचार

इंजीनियर के लॉकरों ने उगले 2 करोड़ कैश

ओडिशा में 5 मल्टीस्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के असिस्टेंट एंजीन्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बेहरा कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी में पदस्थ हैं। उनका 1999 में जुनियर इंजीनियर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ था। तब सैलरी 6 हजार रुपए थी। ओडिशा विजिलेंस को बेहरा के पास आय से ज्यादा



भुवनेश्वर में चार बहुमंजिला

भुवनेश्वर के 4 इलाकों के अलावा जाजपुर जिले के धर्मशाला स्थित पैतृक घर, रिशतेदारों के आवास, सरकारी क्वार्टर और ऑफिस में भी तलाशी ली गई। कार्रवाई में 2 एडिशनल एसपी, 5 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और बड़ी संख्या में अन्य अधिकारियों को लगाया गया। जांच में अब तक पांच बड़ी इमारतों का पता चला है।

संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) के सर्च वारंट के आधार पर विजिलेंस ने शुरूवार को भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल जिले के कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 5 बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लॉट, सोने के गहने और बैंक लॉकरों से करीब 2.4 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। सभी संपत्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाइयों में एक माना जा रहा है।

पार्टी का विलय कीजिए या किनारे लग जाइए!

बीजेपी ने उपेन्द्र कुशवाहा को दे दिया सख्त ‘मैसेज’

पटना (एजेंसी)। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में टिकट क्यों नहीं दिया। एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब 8 जून को कोई चमत्कार हो जाए तो अपार बात है, लेकिन फिलहाल दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में पड़ गया नजर आ रहा है। छह महीने के अंदर किसी सदन के



सदस्य बनने की संभावना अब धूमिल होती दिख रही है। अभी जो सामने तस्वीर है उसके हिसाब से कुछ दिनों में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि भाजपा अब आर-पार के मूड में है। मार्च में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भाजपा ने उपेन्द्र कुशवाहा के सामने शर्त रखी थी कि यदि वे अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भाजपा में विलय कर लेते हैं तभी उनकी राज्यसभा में और दीपक प्रकाश को विधान परिषद में भेजा जाएगा। उपेन्द्र कुशवाहा राज्यसभा में चले भी गये। भाजपा ने उनकी जीत को सुनिश्चित जीत के लिए चौथा उम्मीदवार बनाया था। कुशवाहा के लिए भाजपा ने खुद अपने उम्मीदवार शिवेश राम को पांचवां उम्मीदवार बना कर चुनौतियों से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। भाजपा की इस दरियादिली के बाद भी रालोमो का भाजपा में विलय नहीं हुआ।

नीट पेपर लीक के बाद

बदलेगा एनटीए का सिस्टम

एक्सपर्ट्स सवाल तैयार तो करेंगे,पर पता नहीं होगा किस एजाम के लिए किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है, जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें करीब 10 हजार सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्नीक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा। वहीं, शनिवार को अखबार के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। मंत्री जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।



रिजिजू बोले- शिक्षा मंत्री पर सीधा आरोप हो तो इस्तीफा मांगिए

रिजिजू ने कहा कि लाखों छात्रों को नीट दोबारा देने की नौबत आई और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों से भी परेशानी हुई। ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी समस्या को ठीक करना है, न कि उससे बचना। उन्होंने भरोसा जताया कि उठाए गए कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री या उसके स्टाफ पर सीधे भ्रष्टाचार, रिश्तत या गलत काम का आरोप हो तो इस्तीफे की मांग जायज होती है।

एनटीए बोला- नीट री-एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ

नीट 2026 री-एग्जाम से पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर पेपर लीक होने और सवाल पहले से मिलने के कई दावे किए जा रहे हैं। एनटीए ने इन सभी दावों को गलत और भ्रामक बताया है। एजेंसी का कहना है कि कुछ टग गिरीह छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पेपर और लीक से जुड़े मैसेज पूरी तरह फर्जी हैं। एनटीए ने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। एजेंसी ने छात्रों से अफवाहों पर भरोसा न करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही, ऐसे फर्जी मैसेज और पोस्ट फैलाने वाले अकाउंट्स व चैनलों की पहचान की जा रही है।

गौतम अडानी 1, मुकेश अंबानी 2

एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर 89.2 अरब डॉलर हो गई है। यह उन्हें एशिया में सबसे अमीर



की रियल-टाइम बिलेनियर्स लिस्ट में यह जानकारी दी गई। अडानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर के साथ

दूसरे नंबर पर हैं। सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन को 87 अरब डॉलर के साथ तीसरा पायदान मिला है। सोन गुरुवार को जापानी निवेश फर्म के शेयरों में गिरावट से पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे।

कानूनी चुनौतियों से उबर चुका है अडानी ग्रुप

अरबपति उद्योगपति ने पिछले महीने शेरशर्धारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में कहा कि अडानी समूह अमेरिकी कानूनी चुनौतियों से उबर चुका है। ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रहा है। इससे वह एआई आधारित विकास की बढ़ती मांग से फायदा उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के हालिया 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की सफलता को निवेशकों का विश्वास बताया।

हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद आई थी गिरावट

अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और व्यापक धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि, भारतीय नियामकों ने पिछले साल इन दावों को खारिज कर दिया था। कहा था कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। उन्हें अमेरिका में भी आरोपों का सामना करना पड़ा था। ये अब समाप्त हो चुके हैं।

बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में रार

डीएमके-एएपी का बहिष्कार,बैठक से कर लिया किनारा

नई (एजेंसी)। सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में सीपीआई (एम) का प्रतिनिधित्व पार्टी के राज्यसभा नेता जॉन ब्रिट्टास करेंगे। हालांकि, केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगे आरोपों को लेकर पार्टी अभी भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले



से बताया कि सीपीआई (एम) के महासचिव एम.ए. बेबी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को पत्र लिखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उन

टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिनमें केरल में सीपीआई (एम) और बीजेपी के बीच राजनीतिक समझ होने का संकेत दिया गया था।

गठबंधन की भावना के खिलाफ आरोप

लेटर की कॉपी इंडिया ब्लॉक के दूसरे हिस्सों के साथ भी शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे आरोप विपक्षी गठबंधन की सहयोग की भावना के खिलाफ हैं। लेफ्ट पार्टी ने कहा है कि वह इस मामले पर कांग्रेस से सफाई का इंतजार कर रही है। सीपीआई (एम) के सूत्रों ने कहा कि पार्टी को अभी तक कांग्रेस से कोई जवाब नहीं मिला है और उम्मीद है कि ब्रिटिस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे।

घर के चूल्हे में फिर लगी ‘महंगाई’ की आग

घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह तीन महीने में दूसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि सरकारी ईंधन कंपनियां बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागत से जूझ रही हैं। दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 9113 रुपये से बढ़कर 942 रुपये



हो गई है। यह नई दर 7 जून से लागू हो गई है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, मार्च में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके चलते 7 मार्च को 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। दूसरे ईंधनों की कीमतों में भी वृद्धि एलपीजी की इस बढ़ोतरी के साथ ही अन्य ईंधनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.50 प्रति लीटर रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। सीएनजी की दर में करीब 6 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद तेल कंपनियां पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.60 रुपये प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं।

मुद्दे को लेकर

दोनों दलों में विवाद

इस बातचीत में, बेबी ने चिंता जताई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा और खरगे समेत कांग्रेस नेताओं के आरोप चुनावी आलोचना से कहीं आगे थे, जिससे बीजेपी को मिलकर चुनौती देने के लिए बने गठबंधन के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए। केरल विधानसभा चुनावों के बाद से ही यह मुद्दा दोनों पार्टियों के बीच विवाद का विषय रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करने की साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

इसे कहते हैं मां का बाजार

इस बाजार का नाम है, इमा कीथला। हिंदी में कहें तो मां का बाजार। माना जाता है कि यह सभी दुकानें 500 साल पुरानी हैं और एशिया में महिलाओं के सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जानी जाती हैं। मणिपुर सरकार और विभिन्न ऐतिहासिक अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि इस बाजार का इतिहास 16वीं सदी के राजा खगेम्बा से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि बाजार का विकास आंशिक रूप से पुराने मणिपुरी ‘लल्लूप-कन्बा’ सिस्टम के चलते हुआ। इस सिस्टम में कई पुरुषों को समय-समय पर सेना में काम करने या जबर्न मजदूरी के लिए भेजा जाता था। पुरुषों की गैरमौजूदगी में महिलाएं व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां चलाती थीं। समय के साथ, इस पर महिलाओं का ही पूरा नियंत्रण हो गया।

इंफाल (एजेंसी)।

मणिपुर पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन यहां की राजधानी इंफाल के एक बाजार के बारे में आप नहीं जानते होंगे। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर सभी दुकानें केवल महिलाएं ही रन करती हैं। इनकी संख्या भी कोई सौ-दो सौ नहीं है, बल्कि हजारों में है। यह महिलाएं, सब्जियों, मछली, मसालों, कपड़ों, हाथ से बने सामान, ज्वेलरी और घर के सामान की अन्य दुकानों पर बैठती हैं। यह सभी दुकानें सुबह-सुबह खुल जाती हैं और देर रात तक सामानों की खरीद-फरोख्त चलती रहती है।



युद्ध से भी कनेक्शन

इसे चलाने वाली महिलाएं ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाएं भी निभाती रही हैं। मणिपुरी महिला व्यापारियों ने मशहूर नूपी लान, या महिला युद्ध हिस्सा लिया था। यह युद्ध 1904 और 1939 के दौरान हुए थे, जब महिलाओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और आर्थिक शोषण का विरोध किया। इसलिए बाजार न केवल एक कॉमर्शियल हब के तौर पर विकसित हुआ बल्कि सामूहिक राजनीतिक सक्रियता के लिए भी जाना गया।

5000 से अधिक महिला विक्रेता

अनुमान के मुताबिक आज इंफाल के इस बाजार में 5,000 से अधिक महिला विक्रेता काम करती हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाजार का मैनजमेंट पूरी तरह से महिलाएं ही संभालती हैं। इनमें से कई परिवारों में पीढ़ियों से स्टॉल विरासत में मिले हैं। कई दुकानें तो ऐसी हैं, जिन्हें मां ने अपनी बेटियों को सौंप दिया है। इस तरह यह काम पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता चला आ रहा है।

अरबिंदो अस्पताल से नगर निगम ने 25 कुत्ते पकड़े, पर काटने वाला नहीं मिला

आवारा कुत्ते का आतंक, 40 से अधिक लोगों को घायल किया



इंदौर। सांवर रोड क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते के हमले से शुक़वार को अफरा-तफरी मच गई। कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया। शनिवार को नगर निगम ने इलाके में कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया, जिसमें 25 कुत्ते पकड़े गए। लेकिन, बताया गया कि लोगों को काटने वाला कुत्ता अभी भी हाथ नहीं आया।

कुत्ते के हमले से घायल होने वालों में अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंगर्मी, मेडिकल स्टूडेंट, मरीज, सुरक्षा कर्मी और राहगीर शामिल हैं। इनमें 16 से अधिक लोग अरबिंदो अस्पताल से जुड़े बताए गए। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे कुत्ता अरबिंदो अस्पताल के पिछले हिस्से से परिसर में घुसा और सबसे पहले वहां मौजूद कर्मचारियों पर हमला किया। इसके बाद वह अस्पताल परिसर से निकलकर सांवर रोड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुंचा और रास्ते में मिलने वाले लोगों को काटता गया।

अभी तक 25 कुत्तों को पकड़ा

घटना के बाद शनिवार को नगर निगम की दो दलों ने अरबिंदो अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया। घेराबंदी कर अब तक 25 कुत्तों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन लोगों को घायल करने वाला कुत्ता अभी तक पकड़ में नहीं आया है। निगम की टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। कुत्ता अस्पताल परिसर से निकलकर रेवती रेंज, बरदरी गांव, एलएनसीटी महाविद्यालय, रेनेसां महाविद्यालय, नरसीमुंजी महाविद्यालय तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया था। इस घटना के बाद गांवों और शिक्षण संस्थानों में भय का माहौल है। कई लोग अकेले आने-जाने से बच रहे हैं, जबकि अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

ग्रीष्मकालीन शिविर में सुरक्षा के गुर सिखाए

इंदौर। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा गारमेंट पब्लिक स्कूल में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल शिविर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। सहायक पुलिस आयुक्त सुप्रिया चौधरी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में सुबेदार अशोक भागवत और उनकी टीम ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग की अनिवार्यता, ट्रैफिक सिग्नल,नियमों की अन्देखी से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया गया। सुबेदार ने कहा कि सड़क पर छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार, आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने वाले धराए

इंदौर। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने डिलीवरी बॉय से मोबाइल लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा मोबाइल भी बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को दिन नगर क्षेत्र में डिलीवरी बॉय पासल पहुंचाने गया था। उसी दौरान वह मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी दो युवक उसके पास पहुंचे और अचानक मोबाइल छीनकर भाग गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी गणेश और निखिल ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।आरोपियों से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से एक-एक मामला दर्ज है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वे अन्य किसी लूट, चोरी या आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं या नहीं।

दुष्कर्म मामले में पुलिस लापरवाह, चक्काजाम

इंदौर। पिछले दिनों गांधीनगर थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। लेकिन, मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया। यहां तक कि मेडिकल करवाना भी उचित नहीं समझा। पुलिस की इस लापरवाही के खिलाफ बच्ची के परिजनों ने बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शुक़वार देर रात थाने का घेराव कर चक्का जाम किया था। पुलिस ने बच्ची ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र के ही अथेड़ युवक को गिरफ्तार किया था। जब इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी, तो उन्होंने गोमटगिरी चौराहे पर चक्काजाम किया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल भी नहीं करवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है कि मामले में धारा बढ़ाई जाए। जो आरोपी है, उन्हें भी गिरफ्तार कर जुलूस निकाला जाए। मामले में टीआई का कहना है कि बच्ची का मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में एक आरोपी किया है।

गांजे, ब्राउन शुगर के साथ दो को पकड़ा

इंदौर। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आजाद नगर और भंवरकुआ पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा। तस्करों से बड़ी मात्रा में गांजा और ब्राउन शुगर जब्त किया है। भंवरकुआ थाना प्रभारी संतोष दूधी द्वारा चैकिंग और संदिग्धों को चैकिंग के लिए टीम गठित कर क्षेत्र में रवाना किया। टीम भ्रमण के दौरान आईटी पार्क चौराहा होता हुआ राजीव गांधी चौराहे तरफ आगे बढ़ी। तभी आईटी पार्क नवनिर्माण ब्रिज के पास टीम को संदिग्ध युवक दिखा। जो पुलिस को देख कर भागने लगा।शंका होने पर पुलिस ने संदेही को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 327 ग्राम गांजा जब्त किया। मामले में तस्कर देवराज पिता अनिल चौहान निवासी एलआईजी चौराहा को पकड़ा। इसी प्रकार, आजाद नगर पुलिस ने 10.02 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी सैयद अली को गिरफ्तार किया है। तस्करों से मादक पदार्थ को लेकर पूछताछ की जा रही है।

घायलों को टीके लगाए गए

हमले में घायल 40 से अधिक लोगों का उपचार अरबिंदो अस्पताल सहित अन्य चिकित्सालयों में किया गया। सभी को रेबीज रोधी टीके सहित आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया। अरबिंदो अस्पताल में उपचार प्राप्त करने वालों में डॉ स्मृति, डॉ अश्विता, सचिन राजपूत, अंजनी शर्मा, सीमा, शोभा, परिणीता, कुसुम, प्रणव गुप्ता, गोविंदा, विष्णु, अफसर, राजीव धाकड़ और आर्यन सहित अन्य लोग शामिल हैं। स्थानीय नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम से हमलावर कुत्ते को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक वह कुत्ता पकड़ में नहीं आता, तब तक क्षेत्र में लोगों के मन से डर समाप्त नहीं होगा।

शहर में रोज 200 घटनाएं

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि खोज अभियान जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दल भी लगाए जाएंगे। साथ ही नागरिकों से किसी भी संदिग्ध कुत्ते की जानकारी तुरंत निगम के नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की गई है। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शासकीय हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक (लाल अस्पताल) के प्रभारी डॉ रुपेंद्र पटेल के अनुसार, अस्पताल में प्रतिदिन करीब 200 लोग कुत्तों के काटने के उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। यह आंकड़ा शहर में बढ़ती समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

विवाद के चलते भाई ने ही की थी हत्या मृतक की पत्नी को फंसाने की साजिश

परिवार ने मृतक की पत्नी शीतल पर चाकू मारने का आरोप लगाया

इंदौर। तीन दिन पहले पारिवारिक विवाद में हुई युवक की हत्या में उसका भाई शामिल था। भाई के इस कृत्य में मदद करने वालों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। आरोपी मृतक की पत्नी को झूठे प्रकरण में उलझाने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई।

4 जून को सूर्यदेव नगर के नाथ मोहल्ला में हुई हत्या का है। घटना में घायल हरीश पिता नरेन्द्र सितोले निवासी सूर्यदेव नगर की हत्या हुई थी। पहले यह हत्याकांड संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हो गया। द्राकपुरी पुलिस के अनुसार, घटना के बाद मृतक की मां पुष्पा एवं आसपास की कुछ महिलाओं ने थाने पहुंचकर शुरू में मृतक की पत्नी शीतल पर चाकू मारने का आरोप लगाया था।

जांध पर वार कर दिया

पत्नी के थाने के जाने के बाद हरीश घर पहुंचा और पत्नी के साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध किया। इससे उसका प्रद्युम्न एवं नरेन्द्र ने विवाद हो गया। विवाद के दौरान प्रद्युम्न ने चाकू से हरीश की जांध पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद आरोपीगण घायल हरीश को एमबाय अस्पताल ले गए और डॉक्टरों को भ्रामक जानकारी दी कि वह पहली मंजिल से गिरकर घायल हुआ है। जहां उसकी अधिक रक्तस्राव होने से मृत्यु हो गई थी।

हत्या के बाद खून साफ किया

हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने, मृतक की पत्नी को झूठे प्रकरण में फंसाने का षड्यंत्र रचा। आरोपी पुजा ने घटनास्थल से खून साफ किया और घटना में प्रयुक्त चाकू को छिपा दिया। परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने अलग-अलग एवं विरोधाभासी कथन दिए गए। पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों सहित सभी तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। इसमें यह साबित हुआ कि हरीश को प्रद्युम्न ने चाकू मारा था। मामले में पुलिस ने प्रद्युम्न पिता नरेन्द्र, दीक्षा पति शिवम चावड़ा, पूजा पति प्रद्युम्न शितोले, पुष्पा पति नरेन्द्र शितोले, नरेंद्र पिता मांगीलाल शितोले को गिरफ्तार कर लिया है।

खुद को चाकू मारने की बात कही

बाद में जब यह स्पष्ट हुआ कि घटना के समय शीतल थाना परिसर में उपस्थित थी। तब परिजनों ने अपना कथन बदलते हुए हरीश द्वारा खुद को चाकू मारने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई। शिकायत करने को कहा था, जांच में यह तथ्य सामने आए कि घटना के समय घर पर मृतक के पिता नरेन्द्र, मां पुष्पा, भाई प्रद्युम्न, भाभी पूजा, बहन दीक्षा तथा पत्नी शीतल मौजूद थी। शीतल के चरित्र को लेकर परिवार में विवाद हुआ। इसके बाद प्रद्युम्न एवं नरेन्द्र ने उसे घर से निकाल दिया था। शीतल ने इसकी सूचना अपने पति हरीश को दी। हरीश ने उसे थाने जाकर शिकायत करने को कहा था।

छावनी रोड चौड़ीकरण पर कांग्रेस का आक्रोश, मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन



उज्जैन में दोगुना मुआवजा, इंदौर में क्यों नहीं, व्यापारियों का बड़ा विरोध

इंदौर। छावनी क्षेत्र में नगर निगम की रोड चौड़ीकरण कार्रवाई के खिलाफ शनिवार शाम कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दो दशक से अधिक समय बाद पुराने व्यापारिक क्षेत्र छावनी में व्यापारियों और रहवासियों का इतना बड़ा विरोध देखने को मिला।

प्रदर्शन को स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, व्यापारी और रहवासी रैली एवं सभा में

शामिल हुए। छावनी चौराहे पर आयोजित सभा में व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर वर्षों पुरानी दुकानें और मकान तोड़ दिए गए। व्यापारी विवेक पाटनी, विक्की मित्तल और प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि यदि उज्जैन में प्रभावितों को दोगुना मुआवजा दिया जा सकता है और किसानों को भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा मिलता है, तो छावनी के व्यापारियों और नागरिकों को भी

उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

पक्षपात और मनमाना के आरोप- रहवासियों ने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े कुछ लोगों की इमारतों को कार्रवाई से बचाया गया, जबकि आम नागरिकों को राहत या स्टे लेने का अवसर तक नहीं मिला। लोगों ने मांग की कि सड़क की चौड़ाई और अधिग्रहण संबंधी स्थिति को लेकर स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए।

शहर में गर्मी और उमस में बढ़ोतरी, दिन का तापमान 2 और रात का 1 डिग्री चढ़ा

मानसून की आहट तेज, 20 जून से पहले मध्य प्रदेश पहुंचने के संकेत

इंदौर। शहर में गर्मी और उमस का असर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रात का तापमान 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रविवार सुबह से आसमान पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप निकलने से लोगों को उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ा। जून के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज अपेक्षाकृत नरम रहा है। इस दौरान चार दिनों तक दोपहर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। वहीं 4 जून को रात का तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वर्तमान में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम है, जबकि रात का तापमान सामान्य स्तर पर बना हुआ है।

20 जून से पहले मानसून - इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आने बढ़ रहा है। केरल में प्रवेश के बाद मानसून ने तेजी पकड़ी और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब इसके जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन सामान्य



समय से पहले हो सकता है और इसके 20 जून से पहले प्रदेश में पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 15 जून मानी जाती है। आमतौर पर मानसून दक्षिणी हिस्से से मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। वर्ष 2025 में मानसून एक दिन की देरी से 16 जून को प्रदेश में पहुंचा था और इसकी विदाई 15 अक्टूबर तक हुई थी। सामान्य परिस्थितियों में केरल पहुंचने के लगभग 15 दिन बाद मानसून मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे देता है। इस वर्ष केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है, इसलिए इसके जल्द प्रदेश में आने की संभावना जताई जा रही है।

जून में गर्मी क्रम हुई - जून महीने के मौसम के आंकड़े बताते हैं कि पिछले सात साल में इंदौर में इस महीने भीषण गर्मी अपेक्षाकृत कम रही है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच जून में अधिकतम तापमान 39.6 से 41.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। पिछले वर्ष अधिकतम तापमान

41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। बारिश के लिहाज से भी जून का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान सामान्यतः पूरे मासिक वर्षा कोटे का लगभग 20 प्रतिशत पानी बरस जाता है। पिछले वर्ष जून में शहर में साढ़े 5 इंच वर्षा दर्ज की गई थी। वहीं वर्षा के पुराने अभिलेखों पर नजर डालें तो वर्ष 1980 में जून महीने में 17 इंच से अधिक वर्षा हुई थी। 23 जून 2003 को 24 घंटे में 5 इंच पानी गिरने का कीर्तिमान बना था।

क्या कहता है रिकॉर्ड -

तापमान के पुराने रिकॉर्ड भी उल्लेखनीय हैं। 3 जून 1991 को इंदौर में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि 12 जून 1958 को न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिलहाल शहरवासियों की निगाहें मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि इसके आगमन के साथ ही उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी।

लाखों का माल उड़ाने वाला गिरफ्तार



इंदौर। भंवरकुआं थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्णावत पान दुकान में हुई चोरी का महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। खंडवा नाका स्थित दुकान का टीन शेड तोड़कर सिगरेट, गुटखा,लाइटर एवं अन्य सामान चोरी करने वाले शांतिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एक विधि-विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात के बाद टीम ने क्षेत्र के करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और सूचना के आधार पर जीतू उर्फ राइडर (19) निवासी कमल नगर,मूसाखेड़ी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया सामान बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अन्य चोरी की घटनाओं में उसकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस सफलता में थाना प्रभारी एवं भंवरकुआं पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने इसे संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

फिर तोड़फोड़ का डर

प्रभावित परिवारों ने आशंका जताई कि यदि वे वर्तमान सीमा के अनुसार निर्माण करते हैं तो भविष्य में मास्टर प्लान का हवाला देकर दोबारा तोड़फोड़ की जा सकती है। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिट्ठू चौकसे,जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, सत्यनारायण पटेल, रीना बोरसी,विनय बाकलीवाल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

संपादकीय

क्या योगी सरकार पर असर होगा?

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आए दिन होने वाले पुलिस एनकाउंटर पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। यह टिप्पणी सीधे सीधे राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ है, जिसने पुलिस एनकाउंडर और बुलडोजर को ही अपनी पहचान बना लिया है। हालांकि कोर्ट की कड़ई टिप्पणी का योगी सरकार पर कितना असर होगा, कहना मुश्किल है। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस के लिए संविधान नहीं, राजनीतिक आकाओं की खुशी बड़ी है। मलाईदार तैनाती के लिए उन्हें खुश करना ही उनका मकसद है। भले ही इसके लिए उन्हें किसी की अवैध गिरफ्तारी करनी पड़े या फर्जी मुठभेड़, वे करने से नहीं घबराते। उन्हें भरोसा है कि उन्हें उनके आका बचा लेंगे। यही कारण है कि यूपी में कानून का राज नहीं, बल्कि अफसरों की सनक और राजनीतिक आकाओं को खुश करने का खेल अपने चरम पर हैं। इस तल्ख टिप्पणी के साथ साथ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक ही परिवार के पिता - पुत्र और बहू के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत लंबित अपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि 35 वर्षीय गृहिणी ललिता त्यागी को एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाला कोई ठोस आधार अभिलेखों पर मौजूद नहीं था। कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त और वर्तमान में प्रयागराज जोन के आईजी अजय कुमार मिश्रा की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं रखा और गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को स्वीकृति देने में आवश्यक सावधानी नहीं बरती। यह सच्चाई है कि पुलिस के ऐसे कथित एनकाउंटर और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को राज्य सरकार बढ़ावा देती रही है। कुछ मामलों में यह सही भी हो, लेकिन अधिकांश मामलों में तो 'जो हम करें से कायदा' वाली मानसिकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में अफसरों की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है और वे अपनी कुसूरियां बचाने के लिए लक्षित अभियोजन चला रहे हैं। हेरानी की बात यह है कि यूपी में एनकाउंटरो और बुलडोजर पर भी जातीय और साम्प्रदायिक राजनीति हो रही है। विपक्ष इसे जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है। जबकि सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक कुल 207 अपराधी मुठभेड़ में डेर हुए हैं। इसमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 उज्जर, 16 यादव, 17 गुर्जर-जाट, 14 एससी, 3 एसटी, 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य जाति और धर्म के लोगों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। जा चुका है. यह आंकड़ा 2017 से 5 सितंबर 2024 तक का है। इस तरह कुल 138 हिंदू और 67 मुस्लिमों के एनकाउंटर किए गए हैं। इसी तरह सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया? कि राज्य बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, जबकि ऊंची जाति के अपराधियों पर वैसी सख्ती नहीं होती। अखिलेश ने तो यहां तक ​​आगे लगाया कि यूपी में अपराध नियंत्रण अब खुद अपराधियों के हाथों में पहुंच गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भाजपा राज में महाभ्रष्ट शासन-प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटरो ने उस की छाती को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। भाजपा खुद अपराधी है।' उधर योगी सरकार का मानना ​​है कि इस तरह की सख्त कार्रवाइयां उसकी युसुपी है। जनता के बड़े वफा का सम्पन्न उसे प्राप्त है। ऐसे में कोर्ट की टिप्पणियों का उस पर कुछ भी असर होना असंभव है।

स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी से दूर भागती सरकार



मई के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिनकी विवेचना जरूरी है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के 15 लाख स्कूलों का संचालन एक समिति करेगी। जिसमें प्राचार्य शिक्षकों के अलावा 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों के अभिभावक याने तीन चौथाई सदस्य अभिभावक होंगे। यह भी निर्णय किया कि 30 लाख रुपये तक के जो स्कूल-भवन में सार्वजनिक कार्य होंगे वह कार्य यह समिति ही करायेंगी, किसी अनुमति की ऊपर से आवश्यकता नहीं होगी। तथा अब ये शिक्षण संस्थायें सीएसआर से याने कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी के तहत सार्वजनिक या निजी उद्योगों से मदद ले सकते हैं। ऊपरी तौर पर यह निर्णय सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लगता है और शालाओं के संचालन की कुंजी की चाबी मुख्यत अभिभावकों की समिति को देते हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि धन संबंधित चौक आदि पर प्राचार्य के साथ-साथ अभिभावक समिति के अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे। निसंदेह यह निर्णय छात्रों के सबसे शुभचिंतक उनके अभिभावकों को अधिकार देते हैं। परंतु शिक्षा क्षेत्र की जो वास्तविकतायें हैं उनके आधार पर भी सोचना होगा। क्योंकि सरकार का कार्य जमीन पर कम प्रचार पर अधिक चलता है। जैसे कुछ दिनों पहले यह कहा गया था कि नई शिक्षा नीति में प्रति छात्र बजट में 130 प्रतिशत की वृद्धि की गई, याने लगभग सवा गुना परंतु सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नई शिक्षा नीति के बाद कितने स्कूल बंद हुए और कितने छात्रों की संख्या घटी है इसका उल्लेख नहीं किया गया। जबकि तथ्य यह है कि देश में लगभग डेढ़ से दो लाख स्कूल बंद कर दिये और छात्रों की संख्या बहुत घट गए। राज्य सरकारों ने यह तर्क दिया है कि स्कूलों में छात्र नहीं थे या नगण्य थे इसलिये बंद कर दिये गये, तब इस पर भी विचार होना चाहिए कि स्कूलों में छात्र कम हुए तो इसमें किसकी जवाबदेही है। क्या यह तथ्य नहीं है कि देश के 1 लाख स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक, यहां तक की सैकड़ों हजारों स्कूलों में मात्र एक-एक शिक्षक से

स्कूल चलता था और शिक्षक गांव की जगह दूर शहर में रहते थे। इस प्रकार के हालातों के चलते लाचार होकर अभिभावकों को निजी शिक्षण, दुकानों में शरण लेनी पड़ी और जिनकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं थी उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद सत्ता के प्रचारकों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि शिक्षा में बहुत विकास हो रहा और अब सरकार के समक्ष शिक्षा को अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती है। अब यह भी लिखा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद पहले के मुकाबले इन स्कूलों में खेलों के मैदान की सुविधा हो गई जबकि यह पूर्णतरु झूठ है। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया कि खेल मैदानों व जिम आदि की साझेदारी की व्यवस्था हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं उन्होंने दूसरे स्कूलों के साथ खेल मैदान की साझेदारी दिखा दी तथा सरकारी आंकड़ा संतुष्ट हो गया।

सच्चाई यह है कि इस शेयरिंग के नाम पर सरकार ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं को छात्रों की उस मौलिक जरूरत से वंचित कर दिया है याने खेल कूद जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिये आवश्यक है। यही स्थिति पुस्तकालयों की है। मैं कितने ही स्कूलों को देख रहा हूँ कि बच्चों को खेलने की 1 फुट जमीन नहीं है और स्कूलों को इस शेयरिंग के नाम पर सरकार की अनुमति प्राप्त है, तथा यह मनमाना पैसा लूट रहे है। शिक्षा के अंतराष्ट्रीयकरण की चुनौती नहीं है बल्कि चुनौती शिक्षा के स्वदेशीकरण की है। भारत सरकार ने बाकायदा घोषित कर 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में आने की अनुमति दी है। पूर्व से ही विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकारी विवि और निजी विवि लगभग बराबर ही है। या हो सकता है कि निजी विवि कुछ ज्यादा हो।

आज देश में लाखों सरकारी स्कूलों के शाला भवन संस्था में अपर्याप्त है और जो हैं उनमें आवश्यक सुविधायें नहीं हैं। हजारों तो खंडहर में बदल गये। पिछले साल बरसात में मप्र के सागर जिले के शाहपुर कस्बे में एक क्षतिग्रस्त शाला भवन की दीवार गिरने से कई छात्रों की मौत हो गई और सरकार ने अपनी कार्यवाही बताने के लिये आदेश जारी कर दिया कि

जो क्षतिग्रस्त शाला भवन हैं उन्हें गिरा दिया जाये। परंतु यह नहीं सोचा कि अब इन शालाओं के विद्यार्थी कहाँ जायेंगे। और ये शाला भवन कब बनेंगे। मप्र के सागर जिले के सानौधा गांव में मैं पिछले साल दौरे पर गया था, सानौधा गांव सागर जिले का एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव की शाला में आसपास के कई गांव के विद्यार्थियों जिनकी संख्या लगभग 3000 थी पढ़ते थे। वह शाला भवन तो टूट गया, नया बना नहीं, सरकार ने धन राशि दी नहीं और अब बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे हैं। यह तो मैंने एक घटना उद्धृत की है, न जाने इस प्रकार के कितने स्कूल मप्र व देश में होंगे। मप्र में सरकारी स्कूलों में 52 हजार शिक्षक के पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 47 हजार शिक्षक के पद खाली हैं और 7 हजार स्कूल ऐसे हैं

जिसमें केवल एक शिक्षक है। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों की भी है। बिहार में 2.75 लाख, झारखंड में लगभग 1 लाख, प.बंगाल में 77000, शिक्षकों के पद खाली हैं। मप्र के जिन 7 हजार स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, उनमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, कल्पना कीजिये कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? मजदर बात यह है कि, 463 ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं पढ़ता है, परंतु सरकार के अनुसार इनमें 223 शिक्षक पदस्थ हैं। याने बगैर किसी पढ़ाई के शिक्षक वेतन ले रहे हैं। यह स्थिति अकेले मप्र की नहीं है बल्कि लगभग देश के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से की है।

अब यह समितियां बन जायेंगी जिनमें 75 प्रतिशत अभिभावक समिति में सदस्य होंगे परंतु जब स्कूल के भवन के लिये सरकार ने बजट ही नहीं दिया तब यह स्कूल कैसे बनेंगे? कहां से 30 लाख रुपये खर्च करेंगे, (जब पैसा ही नहीं होगा) कुल मिलाकर

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक संतभाकर हैं।



कहा जाता है कि रिशतों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन आज के समय में यह बात धीरे-धीरे बदलती हुई दिखाई देती है। अब बहुत से रिशते विश्वास की गहराई पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिके हुए प्रतीत होते हैं कि हम सामने वाले की कितनी बातें मानते हैं, उसके अनुसार कितना चलते हैं और उसकी इच्छाओं के आगे कितना झुकते हैं। यदि हम उसकी हर बात को स्वीकार करते रहें, उसके विचारों से सहमत होते रहें और उसके अहंकार को चुनौती न दें, तो हम अच्छे कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने विचार रखने लगते हैं या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, रिशतों की परिभाषा बदलने लगती है। जीवन में हम अनेक लोगों से जुड़ते हैं। कुछरिशते जन्म से मिलते हैं और कुछहम स्वयं बनाते हैं। इन रिशतों को संवारने में हम क्यों लगा देते हैं। हम अपनी ओर से पूरी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। हम उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे कारण उन्हें कभी कोई पीड़ा न हो। हमें लगता है कि सच्चाई और समर्पण ही रिशतों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार जीवन हमें एक कड़वा सत्य दिखाता है। यह सत्य यह है कि हर रिशता सच्चाई की कद्र नहीं करता। कुछरिशते ऐसे भी होते हैं जहाँ आपको अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लिया जाता है। आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी मान लिया जाता है और आपका समर्पण एक स्वाभाविक अधिकार समझ

लिया जाता है। ऐसे रिशतों में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता से की जाती है। वहाँ यह नहीं देखा जाता कि आपने कितने वर्षों तक साथ निभाया, बल्कि यह देखा जाता है कि आपने उनकी इच्छा के अनुसार कितना व्यवहार किया।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि चालाकी से बुने गए रिशते अधिक सफल दिखाई देते हैं। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलना जानते हैं, जो शब्दों का जाल बुनना जानते हैं और जो हर व्यक्ति को वहीं सुनाते हैं जो वह सुनना चाहता है, वे अक्सर रिशतों में विजेता दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति सच्चा होता है, स्पष्ट होता है और मन में कुछ तथा मुख पर कुछ और नहीं रखता, उसे कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उसकी सच्चाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक वह अपने आत्मसम्मान से समझौता न कर ले।

लेकिन यहीं सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है,क्या किसी रिशते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग कर देना चाहिए? क्या किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को खो देना उचित है? उत्तर स्पष्ट है , नहीं। रिशते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है, उस दिन वह केवल दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बनकर रह जाता है। उसका अपना अस्तित्व धुंधला पड़ने लगता है।

यह सत्य है कि आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग आसान नहीं होता। कई बार आपको गलत समझा जाएगा, कई बार आपकी नीयत पर प्रश्न उठाए जाएंगे और कई बार वे लोग भी दूर चले जाएंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। उस समय मन टूटता है, निराशा घेरती है और यह महसूस होता है कि शायद सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वास्तव

में सच्चाई का मूल्य तत्काल नहीं मिलता। वह धीरे-धीरे अपना फल देती है।

सच्चाई एक बीज की तरह होती है। जब उसे बोया जाता है, तब वह मिट्टी के भीतर छिपा रहता है। लोग उसे देखकर हँस भी सकते हैं कि यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन समय आने पर वही बीज वृक्ष बनता है, छाया देता है और फल भी देता है। ठीक उसी प्रकार आपको ईमानदारी, आपकी निष्ठा और आपका सच्चा चरित्र भी एक दिन आपके जीवन को संवाराता है। हो सकता है कि आज लोग आपको कद्र न करें, लेकिन आने वाला कल आपके धैर्य और सत्यनिष्ठा का सम्मान अवश्य करेगा।

इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपकी सच्चाई हार रही है और चालाकी जीत रही है, तो निराश मत होइए। जीवन का प्रत्येक परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ जीतें समय के साथ सामने आती हैं। अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़िए, अपनी सच्चाई को मत त्यागिए और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत बेचिए। संसार की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को खो देना सबसे बड़ी हार है।

अंततः जीवन हमें यही सिखाता है कि विश्वास सबसे पहले स्वयं पर होना चाहिए। यदि कोई विश्वास स्थायी है, तो वह आपका अपने चरित्र पर विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, रिशते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आपका सत्य और ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। इसलिए लोगों से प्रेम कीजिए, रिशतों को निभाइए, लेकिन अपनी आस्था का केंद्र केवल दूसरों को मत बनाइए। स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही विश्वास अंततः आपके जीवन को सही दिशा देगा और आपके आने वाले कल को उज्ज्वल बनाएगा।

गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं सभी महासागर



पृथ्वी पर मुख्यतः पांच प्रमुख महासागर हैं, प्रशान्त महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये सभी महासागर न केवल धरती के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये सभी महासागर गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। हर साल 8 जून को 'विश्व महासागर दिवस' मनाया जाता है, जिससे मानव जीवन में समुद्रों की अहमियत, महासागों की साफ-सफाई और उनकी सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाई जा सके लेकिन जिस रफ्तार से समुद्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे यह दिखस केवल एक प्रतीकात्मक आगोश बनकर रह गया है। 'विश्व महासागर दिवस' की वर्ष 2026 की थीम है 'युनर्कल्पना- हमारी जानी-पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया रिसता', जो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि महासागर केवल जलराशि नहीं बल्कि पृथ्वी के जीवन, जलवायु और जैव विविधता के आधार हैं।

दुनियाभर के महासागर बढ़ते मानवीय क्रियाकलापों के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार, औसतन हर मिनेट एक टुक प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फैला जा रहा है। इसके अलावा, भारी मात्रा में सीवेज, औद्योगिक रसायन और जहरीले तत्व भी समुद्रों में पहुंच रहे हैं। अरबों टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में समा जाता है, जो न तो आसानी से विघटित होता है और न ही पूरी तरह समाप्त होता है। यह वही तक समुद्र में पड़ा रहकर समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी को बुरी तरह

प्रभावित करता है। समुद्रों में समाते इन प्लास्टिक कणों और रासायनिक तत्वों का समुद्री वनस्पतियों और जीव-जंतुओं पर बेहद घातक असर पड़ता है। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांस' के मुताबिक, महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जल का पीएच मान घट रहा है, पोषक तत्वों का अपूर्ति प्रभावित हो रही है और ऑक्सीजन की कमी भी स्पष्ट रूप से दर्ज की जा रही है। इन सभी प्रभावों का सीधा असर समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप से भी हर वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं और लवणीय तत्व हिन्द महासागर में प्रवाहित हो जाते हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक कचरे से है, जिसे समुद्री जीव भोजन समझकर निगल जाते हैं। कई बार केल, समुद्री कछुए और डॉल्फिन जैसे जीव मछली पकड़ने वाले जाल या अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि प्लास्टिक में मौजूद विषैले रसायन समुद्री जीवों के शरीर में चले जाते हैं। इन मछलियों और समुद्री जीवों को दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। नार्वे के पास वैज्ञानिकों को 'किलर व्हेल' के चर्बी ऊतकों में पीसीबी जैसे विषैले रसायनों के उच्च स्तर मिले हैं, जो कई देशों में दवाकों पहले ही प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। साथ ही 'पीएफएस' नामक रसायन भी इन जीवों में पाए गए हैं, जो हार्मोन संतुलन, प्रजनन क्षमता और जीवनचक्र पर बुरा असर डालते हैं। वैज्ञानिकों ने व्हेल्स के शरीर में 'ब्रॉमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स' भी खोजे हैं, जो पीढ़ियों में ट्रांसफर होकर अगली पीढ़ी तक जहरीले असर छोड़ते हैं। स्पेनिस नेशनल रिसर्च काउंसिल द्वारा किए गए एक शोध में समुद्री कछुओं के पेट और पशुपेशियों में प्लास्टिक यौगिकों के उच्च स्तर पाए गए हैं। पूर्वी स्पेन के कैटलन तट पर और बेलीएरिक द्वीपों में मृत पाए गए 'लॉगहेड' प्रजाति के 44 समुद्री कछुओं के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आए। इनके शरीर में मौजूद यौगिक हार्मोन सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल और कैंसरजनक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।

महासागरों में प्लास्टिक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया नदियां हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों के जूएँ समुद्रों तक पहुंचता है। 'प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स' रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में 130 मिलियन मीट्रिक टन एकल उपयोग वाला प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। इसमें से केवल 35 प्रतिशत को ही जलाया गया, 31 प्रतिशत को जमीन में दबाया गया और 19 प्रतिशत को खुले में या समुद्रों में फेंक दिया गया। 'साइंस एक्वासेज' जर्नल में प्रकाशित 'ओशियन क्लीनअप' संगठन के अनुसार समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या हजारों में है लेकिन केवल एक हजार नदियां ही 80 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। इन नदियों में से अधिकांश छोटी और मध्यम आकार की हो हैं, न कि केवल विशाल नदियां, जैसा पहले माना जाता था। फिलीपींस, चीन, भारत और मलेशिया जैसी देशों की नदियां समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचाने के मामले में अग्रणी हैं। अकेले फिलीपींस की 4800 नदियां हर साल 3.5 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रों तक पहुंचाती हैं। भारत की 1100 से ज्यादा नदियां हर साल 1.25 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचाती हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण के अलावा जलवायु परिवर्तन भी महासागरों के लिए खतरा बन चुका है। महासागरों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण तूफानों की तीव्रता और संख्या में वृद्धि हो रही है। अरब सागर, जो पहले अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र माना जाता था, अब गर्म हो चुका है। इससे मानसून के पूर्व सत्र में लगातार पांच वर्षों तक चक्रवातों की संख्या में तेजी आई है। अनीपीसीसी की जलवायु वैज्ञानिक डॉ. रोबसी क्रॉम के अनुसार, यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत है और इससे समुद्री पारिस्थितिकी और मानव जीवन दोनों को खतरा है। बहरहाल, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में समुद्रों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक कठोर उपाय अपनाने होंगे। प्लास्टिक उत्पादन, खपत और निपटान को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति और जन-जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी हो गया है। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्रों को सुस्थिति और स्वच्छ बना पाएंगे।

खंगर

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



कौड़ी अब मुहावरों में रह गई है किन्तु कुछ लोग अपनी प्रतिभा से कौड़ी बाजार के हो जाते हैं। माना जाता है कि जो दिन भर झूठ बोले, चाटुकारिता करे, दलाल न हो पर दलाली करे वह फूटी कौड़ी का। पहले भी यही रेट था यही रेट आज भी है। कौड़ी ऐसी मुद्रा है जो किसी दूसरी मुद्रा के मुकाबले उठती गिरती नहीं है। कौड़ी औकात के बाजार में चलने वाली अकेली होती है। कौड़ी का अपना पैमाना है । किसी को पचास लाख रुपए महीना मिल रहा हो तब भी वह दो कौड़ी का हो सकता है।

कोई बहुत सुन्दर हो तब भी दो कौड़ी का हो सकता है। कोई पाँवर फूल हो तब भी इतिहास में उसे 'दो कौड़ी का' कह कर दर्ज किया जाता है। कोई झुटा, बेईमान, ढोंगी, समाज में वैमनस्य फैलाने वाला हो उसे फिक्स

रेट फूटी कौड़ी वाला आईपीओ (IPO) माना जा सकता है। मशहूर माइकल जैक्सन बाल यौन शोषण के आरोप के बाद दो कौड़ी के माने गए । कौड़ी चरित्र पर प्राइज टैग है। इस समय जो 'नोबल शांति' युद्ध चल रहा है उसमें कुछ कौड़ियों नजर आती हैं । इसमें आमतौर पर दो ही रेट होते हैं, फूटी कौड़ी या फिर दो कौड़ी। फूटी कौड़ी प्रायः चलन में कम होती है। कौड़ी क्रम में सबसे नीचे फूटी कौड़ी होती है। फूटी कौड़ी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। फूटी

दूसरों को कुछ भी बोल सकती है।

इतिहास में झाँक कर देखो तो पता चलता है कि वर्षों पहले तमाम लोग जो दो कौड़ी के थे वे आज भी उतने के ही माने जा रहे हैं। संविधान के हस्तक्षेप के बावजूद वे तीन कौड़ी के भी नहीं

कौड़ी का अपना पैमाना है । किसी को पचास लाख रुपए महीना मिल रहा हो तब भी वह दो कौड़ी का हो सकता है।

कोई बहुत सुन्दर हो तब भी दो कौड़ी का हो सकता है।

हो पाए। उनके हितैषी आगे आए और इनों का कारोबार करने लगे लेकिन बनेके भाव नहीं बदले। खरीदने वाले कौड़ियों के मोल में इनकी सहमति खरीदते आ रहे हैं। कौड़ी बाजार में महंगाई नहीं होती है, इसलिए किसी राजनीतिक दल ने कौड़ी को मुद्रा नहीं बनाया है। इधर भक्त-भीड़ पुराने वैभव की ओर लौटने के लिए झइयम-

झइयम-झा कर रहे हैं । उन्हें लगता है

नया भले ही सोने का हो पर उसमें 'वो वाला' वैभव नहीं है। पुराने समय में कौड़ियों से खरीददारी की जा सकती थी। सित्रयां गले में कौड़ी की माला पहनती थी और हाथ, कान,

कमर में भी कौड़ी के जेवर। तो वैभव की श्रेणी में खोना ही पड़ेगा। सोना चाँदी बंद है, सबको पुराने वैभव की ओर

लौटना है । जो लोग लौटना नहीं चाहेंगे उन्हें कली सूची में डाला जा सकता है । नये ज्ञान को हटा कर पुराने के लिए जगह बनाई जाना जरूरी है । हर पुरानी चीज कीमती थी, आज और ज्यादा कीमती है । हालाँकि कुछ उराने-पुराने फैके देने योग्य भी हैं, जैसे पुराने बूड़े नेता या घर में पड़े अपने माँ-बाप या इतिहास

की किताबें, या फिर इतिहास खुद। गंगा जमुना में 'वो वाला' वैभव है, भले ही लैब रिपोर्ट कह रही है कि गंदगी है। कहीं खोदाई में वैभव निकल रहा है तो कहीं कथाओं में वैभव की कल लराउडहपीकर पर चीख रहा है ।

असल में वैभव है या नहीं इस पर अनेक टीवी डिबेट हो सकती हैं । टीवी वाले जानते हैं कि जनता को मूर्ख कैसे बनाए रखा जा सकता है। और टीवी वालों से कैसे काम लिया जाए यह सरकार अच्छी तरह जानती है। पता ही नहीं पड़ता कि टीवी कब सरकार होता है और सरकार कब टीवी ! एंकर आएर आँखें दिखाते खऊवाने दौड़े तो पेनलिस्ट सहम जाते हैं। यह डिबेट का वैभव है। दिसरात टीवी चल रहा है, झूठ नृत्य कर रहा है । एंकर देव कौड़ी वर्षा कर रहे हैं । राजनीतिक किन्नर आशीर्वाद दे रहे हैं। जय जगत, लगे रहो भगत ।

न्याय और कानून

निष्पक्ष चुनाव

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने ताजा फैसले में भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) की वैधता को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि गहन पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एसआईआर करने की शक्ति है। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधिपति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन रिट याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनमें पिछले साल जून में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के लिए जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया का लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था और इन दोनों के बीच सीधा संबंध था।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि जब कानून खुद ही किसी भी समय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और चुनाव आयोग को उचित लगने वाले तरीके से, विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है, तो इस विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं के हरे पहलू के अनुरूप नहीं है। हमारी सुविचारित राय में यह विवादित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है। यह धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक जनदेश में नई जान डालता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर जाकर काम किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद से चार

मीडिया

राजीव खंडेलवाल

लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतुल सुधार न्यास



आज के दौर में मीडिया की शक्ति निर्विवाद है। सरकारों की छवि निर्माण से लेकर जनमत को प्रभावित करने तक उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के उभार से लेकर अन्ना आंदोलन और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उदय तक मीडिया की भूमिका निःसंदेह महत्वपूर्ण रही है। शायद इसीलिए मीडिया से सामान्यतया कोई ‘पंगा’ तब तक नहीं लेना चाहता है, जब तक पानी सिर के ऊपर न निकल जाए।

फिल्मी कलाकार ‘सुरांत सिंह राजपूत’ का मीडिया ट्रयाल हो या ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ जैसी संवेदनशील सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों की अतिरंजित कवरेज जैसे अनेकानेक विषय; पर मीडिया का प्रसारण हर बार एक शब्द गुंजता है ‘‘टीआरपी।’’

टीआरपी क्या है: मीडिया की ‘‘आन बान शान’’ के आकलन का एकमात्र बैरोमीटर ‘‘टीआरपी’’ है। टीआरपी मतलब (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) किसी टीवी कार्यक्रम या चैनल की लोकप्रियता का इकलौता मापदंड है। यह बताता है कि ‘‘लक्षित’’ दर्शकों में से कितने प्रतिशत लोग किसी विशेष कार्यक्रम या चैनल को देख रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो, टीआरपी मीडिया जगत की वह ‘‘मुद्रा’’ (करेंसी) है, जिससे उसका बाजार भाव व रुतबा तय होता है। दूसरे शब्दों में यह व्यापारी के लिए व्यापार की बिक्री के आंकड़े के महत्व के समान है।

टीआरपी का महत्व: किसी चैनल की टीआरपी जितनी अधिक होती है, विज्ञापनदाताओं से उसे महंगे दर पर अधिक

सामयिक

भूपेन्द्र गुप्ता

लेखक कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष हैं।



भारतीय राजनीति में शायद ही कोई नेता ऐसा रहा हो जिसकी आलोचना और चर्चा उनकी हुई हो जितनी राहुल गांधी की। पिछले डेढ़ दशक में उन्हें कभी ‘अनुभवहीन’, कभी ‘अनिच्छुक राजनेता’ और कभी ‘वंशवाद का प्रतीक’ बताया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी राहुल गांधी को "well-intentioned dilettante" कहा था—अर्थात अच्छी नीयत रखने वाला किंतु शौकिया राजनेता। प्रश्न यह है कि क्या यह मूल्यांकन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या समय ने इस निष्कर्ष को चुनौती दी है?

राहुल गांधी के आलोचक प्रायः उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को उनके राजनीतिक जीवन का केंद्रीय तथ्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं। किंतु क्या किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन उसके उपनाम से होना चाहिए या उसके सार्वजनिक जीवन के कार्यों से?

एसआईआर चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार

‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती हैं। यह प्रक्रिया नागरिकता का निर्धारण करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि निर्वासन या नागरिकता कानूनों के तहत समझा जाता है। बल्कि, यह एक चुनावी सत्यापन प्रक्रिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियों में केवल पात्र नागरिक ही शामिल रहें।

दशकों से अधिक का समय बीत जाना, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर नामों का जोड़ा जाना और हटया जाना, तथा तेजी से हुए शहरीकरण और प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में नामों के दोहराव और अशुद्धियों की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए गहन पुनरीक्षण आवश्यक है। प्रक्रिया ने कानून का उल्लंघन नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज किया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950’ और ‘मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960’ के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज किया कि इस प्रक्रिया ने उन लोगों की नागरिकता की धारणा को खत्म कर दिया, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की भी विवेचना की थी कि क्या भारतीय चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने की शक्तियां हैं। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। यह बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि जैसे कई अन्य राज्यों में अभी भी जारी है।

इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस कानूनी सवाल का फैसला करेगा कि क्या भारतीय चुनाव आयोग के पास इस अभ्यास को करने की शक्ति है। इस साल 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ज्यादातर याचिकाएं पिछले साल जून में दायर की गयी थीं, जब भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का फैसला किया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव तथा विभिन्न पार्टियों के कुछ संसदों महुआ मोक्षग, मनोज झा, के.सी. वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले आदि ने ये याचिकाएं प्रस्तुत की थीं। याचिकाकर्ता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण नागरिकता सत्यापन का एक चोर-दरवाजा वाला अभ्यास

याचिकाकर्ताओं ने व्यापक संवैधानिक चुनौती पेश करते हुए यह तर्क दिया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूची के संशोधन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल देता है।

उनका मुख्य तर्क यह था कि यह अभ्यास चुनाव आयोग को असल में नागरिकता का फैसला करने वाली संस्था में बदल देता है। उनके अनुसार, चुनावी पंजीकरण कानून



आयोग को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह उन नागरिकों से, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं, यह मांग करे कि वे दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से अपनी नागरिकता को नए सिरे से साबित करें। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकता से जुड़े सवालों का समाधान केवल नागरिकता अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित कानूनी गणना प्रक्रिया के जरिए। याचिकाकर्ताओं ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन जैसा अभ्यास करार दिया। उनकी ओर से भी यह तर्क दिया गया कि यह अयोग्यता की एक धारणा पैदा करता है। यह मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ डाल देता है। यह प्रक्रिया स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। इससे जुड़ी एक और चिंता यह उठाई गई कि इस प्रक्रिया से ‘लंबित नागरिकता’ की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सत्यापन होने तक मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा

नागरिकता का औपचारिक निर्धारण किए बिना ही, प्रभावो रूप से एक बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गणना प्रपत्रों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या संबंधित चुनावी नियमों के तहत कोई स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं है। इससे यह प्रक्रिया कानूनी रूप से कमजोर हो जाती है। चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 21(3) कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ व्यापक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं देती है। यह प्रावधान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देता है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य किसी बड़े, राष्ट्रव्यापी अभियान के बजाय लक्षित और विशेष हस्तक्षेप करना है।

यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण को उचित ठहराने वाले निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट कारणों को बताने में विफल रहा है। इससे मनमानी की आशंका पैदा होती है।

याचिकाकर्ताओं ने लाल बाबू हुसैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया है कि एक बार किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाने के बाद उसकी नागरिकता के पक्ष में एक धारणा बन जाती है। इसके विपरीत साबित करने का बोझ आपत्ति उत्पाने वाले व्यक्ति पर होता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण इस सिद्धांत को उलट देता है। क्योंकि, यह पहले से ही पंजीकृत मतदाताओं को अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए बाध्य करता है। भारतीय चुनाव आयोग, चुनावी शुद्धिकरण, न कि नागरिकता का निर्धारण।

इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रकृति को मौलिक रूप से गलत समझा है। आयोग का मुख्य तर्क

टीआरपी का मायाजाल, दर्शक भी उतने ही गुनहगार!

मीडिया की ‘‘आन बान शान’’ के आकलन का एकमात्र बैरोमीटर ‘‘टीआरपी’’ है। टीआरपी मतलब (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) किसी टीवी कार्यक्रम या चैनल की लोकप्रियता का इकलौता मापदंड है। यह बताता है कि ‘‘लक्षित’’ दर्शकों में से कितने प्रतिशत लोग किसी विशेष कार्यक्रम या चैनल को देख रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो, टीआरपी मीडिया जगत की वह ‘‘मुद्रा’’ (करेंसी) है, जिससे उसका बाजार भाव व रुतबा तय होता है। दूसरे शब्दों में यह व्यापारी के लिए व्यापार की बिक्री के आंकड़े के महत्व के समान है।

विज्ञापन मिलने से उतनी ही अधिक आय प्राप्त होती है। यही कारण है कि चैनलों के बीच दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की निरंतर गला-काट प्रतिस्पर्धा होकर यह कई बार निम्न स्तर तक चली जाती है।

टीआरपी केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। अधिक दर्शक संख्या चैनल की राजनीतिक दखलंदाजी और सामाजिक प्रभावशीलता भी बढ़ाती है। सत्ता, कॉर्पोरेट जगत और रसूखदार तबके स्वाभाविक रूप से उन मंचों के निकट रहना चाहते हैं, जिनकी पहुंच जनता के बीच व्यापक हो। मीडिया हाउस को भी सत्ता और कॉर्पोरेट जगत के निकट आने का फायदा मिलता है। इसलिए वे उसके आस-पास रहने का प्रयास करते हैं।

टीआरपी की गणना: भारत में टीआरपी की गणना और प्रकाशन BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कॉर्पोरेशन) द्वारा किया जाता है। यह ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजर्स और एजेंसियों का संयुक्त संगठन है। इसके लिए देशभर के चयनित घरों में विशेष उपकरण (people meter) लगाए जाते हैं, जो यह रिकॉर्ड करते हैं कि कौन-सा चैनल कितनी देर तक देखा गया।

इस आंकड़े का विश्लेषण आयु, लिंग, ग्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि तथा सामाजिक-आर्थिक वर्गों के आधार पर ‘‘वेटेज’’ देकर किया जाता है और फिर पूरे देश के दर्शकों का अनुमान

लगाया जाता है। इसी आधार पर साप्ताहिक टीआरपी भी रिपोर्ट जारी होती है।

दोषी कौन: जब भी कोई चैनल किसी घटना को ‘‘राई का पहाड़’’ बनाकर सनसनीखेज तरीके से प्रसारित करता है (कुछ उदाहरण ऊपर दिए गए हैं), तो तुरंत तोहमत



लगती है कि यह सब ‘‘टीआरपी का खेल’’ है। मानो पत्रकारिता की सारी विकृति की जड़ यही एक शब्द है। तथापि यह आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है। लेकिन क्या सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ना ओझा सच को देkhना नहीं? वास्तव में इसी आरोप में जनता की अंशदायी (योगदान), ‘‘सहभागिता’’ भी छुपी हुई है। टीआरपी किसी चैनल के कार्यक्रम में नहीं, बल्कि वह दर्शकों के ड्राइंग रूम में बनती है।

विडंबना देखिये, जिस कटेंट को लोग ‘‘चटकारे लेकर’’ देखते हैं, भरी महफिल में उसको कोसते भी है। मीडिया को कोसना और खुद को ‘‘दूध का धुला’’ बताना अपना ‘‘उल्लू सीधा करना’’ होगा। यहीं से मुद्दे का दूसरा पक्ष सामने आता है।



टीआरपी आती कहाँ से है: यदि दर्शक किसी कार्यक्रम को देखना ही बंद कर दें, तो उसकी टीआरपी स्वतः गिर जाएगी। बाजार का सिद्धांत है ‘‘जो बिकता है, वही बाजार में दिखाई देता है।’’ यदि सनसनी, विवाद, भावनात्मक उत्तेजना और उत्तेजक बहसों वाले कार्यक्रम लगातार ऊंची टीआरपी प्राप्त करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें देख भी रहा है। ऐसे में मीडिया की आलोचना

करते समय दर्शकों की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना वास्तविकता से आंख मूंदना होगा। क्या इसके लिए जनता भी दोषी नहीं है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खरीद कर खाए और फिर केवल हलवाई को मधुमेह के लिए दोषी ठहरा दे।

मीडिया कम जिम्मेदार नहीं: इसका अर्थ यह नहीं कि मीडिया अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाता है। पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं, ‘‘धर्म’’ भी है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों की पसंद का पीछा करना नहीं, बल्कि समाज को तथ्यपरक, संतुलित और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने का सार्वजनिक दायित्व भी है। दर्शकों की कमजोरी को ‘‘कैश’’ करने लगे तो प्रेस का मूल उद्देश्य ही धराशायी हो जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया समाज का दर्पण है, तमाशा नहीं।

टीआरपी की अंधी दौड़ के चलते यदि समाचार, मनोरंजन और फूहड़ मजाक, व्यंग की रेखा धुंधली हो जाए, तथ्यों की जगह उत्तेजना ले ले और ‘‘बहस’’ की जगह ‘‘शोर’’ हावी हो जाए, एक कार्यक्रम का नाम ही ‘‘हल्ला बोल’’ ही है, दंगल, महाभारत, आर-पार है तो पत्रकारिता की साख ‘‘मिट्टी में मिलना’’ तय है।

शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में दर्शक पारंपरिक टीवी मीडिया से हटकर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हुए हैं। सूचना के स्रोत बढ़े

हैं और दर्शकों के पास विकल्प भी।

टीवी दर्शकों के गिरते आंकड़े: हाल में ही अंजना ओम कश्यप ने ‘‘हल्ला बोल’’ कार्यक्रम में प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट के मालिकों के संबंध में कोचिंग माफिया के संबंधन के साथ बहुत ही विवादित टिप्पणी की थी, जो ‘‘आग की तरह’’ वायरल हुई। इसका कारण भी टीआरपी बताया गया। लेकिन शायद यह पहली बार हुआ कि मीडिया के ‘‘हल्ला बोल’’ का जवाब सोशल मीडिया ने भी हल्ला बोल कर दिया। टीवी चैनलस खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसे एक वर्ग ने गोदी मीडिया का नाम दिया, को संभल जाना चाहिए कि उनकी टीआरपी पिछले कुछ सालों में गिरकर कहां पहुंच गई है? लगभग 30 से 40 मिलियन दर्शकों की कमी पिछले 10 सालों में आई है और अगले 10 सालों में यह कमी 70 मिलियन तक पहुंचाने की आशंका है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग पलायन कर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर चला गया है (लगभग चार गुना)। रेवेन्यू में 10 गुना वृद्धि हुई जो 2024 में टीवी रेवेन्यू को पार कर गई। विज्ञापन की कुल आय में लगभग 60 की भागीदारी सोशल मीडिया की हो गई। शायद इसीलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के मामले में रैंकिंग मापने वाली संस्था रूस्रस के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में खिसककर 157 वें स्थान पर आ गया।

टीआरपी के खेल में दोष व दायित्व दोनों साझा हैं। मीडिया वही परोसता है, जिसे देखने वाले मौजूद हैं, (मांग और पूर्ति का सिद्धांत) और दर्शक वही देखते हैं, जो उन्हें लुभाता है।

स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ जनमत दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती।

क्या भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के साथ न्याय हुआ है?

यदि केवल वंशवाद ही कसौटी है, तो भारतीय राजनीति के अनेक दलों और नेताओं की वैधता पर समान प्रश्न उठने चाहिए। लगभग हर बड़े दल में ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी प्रारंभिक राजनीतिक पहचान पारिवारिक विरासत से बनी। किंतु उनके मूल्यांकन में अक्सर उनकी राजनीतिक क्षमता, जनाधार और चुनावी प्रदर्शन को भी महत्व दिया जाता है। राहुल गांधी के मामले में यह उदारता कम दिखाई देती है।

पिछले वर्षों में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अलग प्रकार की राजनीतिक शैली प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ‘भारत जोड़े यात्रा’ और ‘भारत जोड़े न्याय यात्रा’ केवल राजनीतिक अभियान नहीं थे; वे जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के प्रयास भी थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएँ, लगातार जनसंपर्क और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद किसी ऐसे नेता की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसे राजनीति में रुचि नहीं है, यह कहना कठिन हो जाता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राहुल गांधी ने अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक नेता रहे हैं जो

एक बड़ी चुनावी हार के बाद सार्वजनिक जीवन के हाशिये पर चले गए। इसके विपरीत राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विपक्षी चेहरों में बने रहे, लोकसभा में चुने जाते रहे और विपक्षी विमर्श को प्रभावित करते रहे। किसी भी लोकतंत्र में यह स्वयं एक राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। यहीं रामचंद्र गुहा जैसे विश्लेषकों के मूल्यांकन पर प्रश्न उठता है। यदि किसी नेता की सफलता का मापदंड केवल सत्ता प्राप्ति है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का महत्व कम हो जाता है। और यदि सफलता का मापदंड जनसंपर्क, वैचारिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक प्रभाव और सार्वजनिक स्वीकार्यता भी है, तो राहुल गांधी का मूल्यांकन अधिक संतुलित होना चाहिए।

गुहा की आलोचना का एक दूसरा पक्ष भी है। वे कांग्रेस में गांधी परिवार की केंद्रीय भूमिका को भारतीय लोकतंत्र की समस्या मानते हैं। यह एक वैध तर्क है। किंतु निष्पक्ष विश्लेषण की मांग यह है कि वही कसौटी अन्य दलों और अन्य राजनीतिक परिवारों पर भी समान कठोरता से लागू की जाए। यदि किसी दल में वंशानुगत नेताओं की उपस्थिति राजनीतिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है, तो दूसरे दल में वही तथ्य लोकतांत्रिक दोष का पर्याय कैसे

बन जाता है?

राहुल गांधी का मूल्यांकन करते समय यह स्वीकार करना आवश्यक है कि उनकी राजनीति से असहमति संभव है। उनकी रणनीतियों की आलोचना भी की जा सकती है। किंतु उन्हें केवल एक राजनीतिक उपनाम तक सीमित कर देना उनके सार्वजनिक जीवन के वास्तविक प्रयासों की उपेक्षा होगी।

लोकतंत्र में किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन इतिहास करता है, और इतिहास केवल वंश नहीं देखता; वह यह भी देखता है कि कठिन समय में किसने संघर्ष किया, जनता से संवाद किया और अपने विचारों के लिए कितना जोखिम उठाया। राहुल गांधी के समर्थक इसी आधार पर कहते हैं कि उनके बारे में प्रचलित धारणाओं और उनके वास्तविक राजनीतिक प्रयासों के बीच की दूरी को अब नए सिरे से परखा जाना चाहिए।

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी कौन हैं; प्रश्न यह भी है कि क्या भारतीय सार्वजनिक विमर्श उन्हें उसी कसौटी पर परखता है जिस पर वह अन्य नेताओं को परखता है। यदि उत्तर ‘नहीं’ है, तो शायद पुनर्मूल्यांकन का समय आ चुका है।

रामचंद्र गुहा से इतना.तो आग्रह किया ही जाना चाहिए कि जिन राजनीतिक दलों ने वंशवादी प्रतिष्ठा के आधार पर ही दूसरे दलों से नेताओं को तोड़ा और अपने दल में शामिल किया उन पर वे क्या राय रखते हैं।क्या सिंधिया,रीता बहुगुणा,वीरेंद्र सिंह,चौटाला,करण गांधी ,अमरेंद्र सिंह ,पटवा,सखलेचा,राजवीर सिंह,पंकज सिंह,पीयूष गोयल,बांसुरी स्वराज,अनुराग ठाकुर ,अशोक चक्राण, देवड़,प्रवेश वर्मा आदि भी समीक्षा के समानाधार पर कसे जाते हैं? इन सबकी योग्यता इनका परिवार ही है.लेकिन राहुल गांधी ही बौद्धिक पूर्वाग्रहों का आसन शिकार हैं क्यों?

वंश किसी नेता को अवसर तो दे सकता है, लेकिन जनता बार-बार केवल वंश के आधार पर वोट नहीं देती। लोकतंत्र में विरासत प्रवेश-झार हो सकती है, स्थायित्व नहीं। राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, उनकी राजनीति से असहमत रहिए, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन के दो दशकों के संघर्ष, यात्राओं और जनसंवाद को केवल एक उपनाम में समेट देना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। तब तो और भी नहीं जब न्यायाधीश इतिहासकार के रूप में जाना जाता हो।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर श्री वानखड़े की अध्यक्षता में एनसीओआरडी की बैठक सम्पन्न



दतिया (निप्र)। कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में विगत दिवस न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में एनसीओआरडी (नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खण्डेलवाल, वन मण्डलाधिकारी मोहम्मद माज, जिला आबकारी अधिकारी दतिया श्री बीएल दांगी सहित अन्य सदस्यगण, पुलिस, प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्तियों के बारे में आसूचना, सूचना का आदान-प्रदान किये जाने। जिले में अफीम, भांग आदि की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने, ऐसे प्रकरण जो क्रास-स्टेट संबंधी हों, उनकी जांच की प्रगति की निगरानी किये जाने। स्कूलों एवं कॉलेजों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देने, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों और दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने। जिले में मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम लागू करने व जिले में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का पर्यवेक्षण करने आदि बिन्दुओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा बैठक में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बीरा में अवैध उर्वरक भंडारण पर कार्रवाई

124 बैग उर्वरक जब्त, बिना लाइसेंस भंडारण एवं विक्रय के मामले में प्राथमिकी दर्ज



शिवपुरी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने समस्त एसडीएम को खाद्य की कालाबाजारी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। गत दिवस पिछोर एसडीएम श्रीमती ममता शाक्य ने ग्राम वीरा में अवैध उर्वरक भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही की है। एसडीएम पिछोर श्रीमती ममता शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ब्रजमोहन (मुन्ना गुप्ता) पुत्र भैयालाल गुप्ता निवासी ग्राम बीरा की दुकान एवं गोदाम की जांच की गई। संबंधित व्यक्ति को दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं हुआ तथा मोबाइल फोन बंद पाया गया।कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा पंचों की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 124 बैग उर्वरक भंडारित पाया गया, जिसमें यूरिया (एनएफएल कंपनी) 94 बैग, एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट अन्नदाता) 27 बैग एवं एनपीके (20:20:0:13) पीपीएल नवरत्न 3 बैग शामिल हैं।बिना लाइसेंस किया जा रहा था उर्वरक का भंडारण एवं विक्रयजाने में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना वैध उर्वरक अनुज्ञप्ति के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

सहायक कोषालय अधिकारी ने मां की स्मृति में किया पौधारोपण

अशोक नगर (निप्र)। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला कोषालय कार्यालय में पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी श्री अशोक राणा ने कलेक्ट्रेट परिसर मे मां की स्मृति में बरगद का पेड़ लगाया। यह पेड़ ऐसे स्थान पर लगाया जिसकी छाया का लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का स्वर्गवास 21 मई को हो जाने के कारण माँ की स्मृति मे एक पेड़ लगाया और जिले मे पदस्थापना तक वृक्ष की देख रेख करने की भी जिम्मेदारी ली।

एसडीएम चांचौड़ा ने खाद वितरण केंद्रों का किया निरीक्षण



गुना (निप्र)। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी चांचौड़ा श्री रवि मालवीय ने चांचौड़ा-बीनानागंज स्थित मार्कफेड गोदाम, डबल

लॉक केंद्र चांचौड़ा एवं सहकारी समिति पैंची के खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई-टोकन आधारित खाद वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई। लंबित टोकनों एवं खाद

स्व सहायता समूहों ने पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प,हर दीदी 5-5 पेड़ लगाएंगी

अशोक नगर (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्गत मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला अशोक नगर अंतर्गत समस्त पंचायतों में स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं एक पेड़ मां के नाम हेतु जनजागरूकता अभियान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान समूह सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे लगाए गए एवं लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल संरक्षण करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

आरोह-26 वीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को ध्यान एवं स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक



मुरैना (निप्र)। आरोह-26 वीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को खिलाड़ियों के लिए ध्यान, स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवनशैली विषयक प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पद्मेश उपाध्याय भी उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 600 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। अपर कलेक्टर श्री रावत ने खिलाड़ियों को ध्यान (मेडिटेशन) का

अभ्यास कराया तथा हर्टफुलनेस पद्धति के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शारीरिक क्षमता के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के नियमित अभ्यास से

एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है, जिससे खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर बेहतर ढंग से केंद्रित रह पाते हैं। उन्होंने बताया कि देश-विदेश के अनेक सफल खिलाड़ी ध्यान एवं हर्टफुलनेस जैसी पद्धतियों को अपनाकर अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार कर रहे हैं।

उन्होंने खिलाड़ियों को संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम तथा सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह भी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मेश उपाध्याय ने खिलाड़ियों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी।

● अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, वैध परियोजनाओं को मिलेगा प्रशासनिक सहयोग

सस्ती और सुविधायुक्त कॉलोनियां विकसित करें: कलेक्टर

हर परिवार का घर का सपना पूरा हो



सहयोग मिलेगा, जबकि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कॉलोनी नहीं, बेहतर जीवनशैली विकसित करें : कलेक्टर ने कहा कि भविष्य की कॉलोनियों में केवल सड़क, बिजली और पानी ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खाना बनाने, कपड़े धुलाई, साफ-सफाई, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत जैसी सेवाएं कॉलोनी स्तर पर उपलब्ध करने के मांडल विकसित किए जाएं, जिससे रहवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

में स्वीकृत एवं वैध कॉलोनियों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे वैध परियोजनाओं में ही निवेश या मकान खरीदने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल अवैध कॉलोनियों की प्रवृत्ति को भी रोकने में मददगार होगी।

सिंगल विंडो सिस्टम से आसान होगी प्रक्रिया: बैठक में कॉलोनी विकास से जुड़ी अनुमतियों एवं विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि इसके तहत एक नोडल अधिकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं का समन्वय किया जाएगा, जिससे कॉलोनाइजर्स को अनावश्यक देरी और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

वैध कॉलोनियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी : कलेक्टर ने कहा कि जिले

विश्व पर्यावरण दिवस पर मुरैना जिले में किया गया पैधारोपण

मुरैना (निप्र)। वश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, चंबल संभाग के संभागीय समन्वयक श्री धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं जिला समन्वयक श्री सतीश सिंह तोमर के निर्देश तथा मुरैना विकासखंड के ब्लॉक समन्वयक श्री अनिल मोदी के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था 'मुरैना युथ अकादमी' द्वारा ग्राम जेवरा खेड़ा, सेक्टर माता बरैया में पर्यावरण संरक्षण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) डॉ. विवेक शर्मा, संस्था प्रतिनिधि श्री संदीप सेगर, सीएमसीएलडीपी अंतर्गत संचालित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम की मेंटर श्रीमती सायरा जैन, आशा कार्यकर्ता श्रीमती कस्तूरी देवी, श्रीमती



ममता कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। पीजी कॉलेज में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने किया पौधारोपण

भिण्ड (निप्र)। विश्व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिण्ड विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) श्री वी.आर. सिरसाम एवं रंजर श्री वसंत शर्मा की उपस्थिति में करीब आधा सैकड़ा पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर डीएफओ श्री वी.आर. सिरसाम ने वनकर्मियों को

पौधारोपण की वैज्ञानिक पद्धति की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि फलदार एवं अन्य पौधों के लिए लगभग 45 सेंटीमीटर गहराई तथा समान लंबाई-चौड़ाई का गड्ढा तैयार किया जाता है, जिससे पौधे का विकास बेहतर ढंग से हो सके। उन्होंने पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा एवं देखभाल के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। भिण्ड

पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कलेक्टर महोदय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर विद्युत प्रबंधन एवं उपभोक्ता सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोषण गर्मी एवं लगातार बढ़ते तापमान के बीच निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में जुटे लाइनमैन एवं मैदानी कर्मचारियों की कलेक्टर महोदय ने विशेष प्रशंसा की।

शासन आपके द्वार, समाधान आपका अधिकार : शिकायतों का मौके पर कराया निराकरण

संपर्क अभियान शिविर में कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं



सहभागिता को मजबूत करना है।'

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे विद्युत विभाग द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं एवं सुझावों को विभाग तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिजली शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार एवं आधुनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। ऐसे में विद्युत संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने विद्युत चोरी के

विरुद्ध जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि सफेद तार अथवा अन्य किसी भी माध्यम से अवैध विद्युत उपयोग कानूनन अपराध है तथा इससे विभाग एवं ईमानदार उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होता है। कलेक्टर ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना उपलब्ध है, वहां घरेलू विद्युत कनेक्शन मात्र 5 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में पात्र बीपीएल परिवार भी मात्र 5 रुपये में घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

घर-घर जाकर इस नवीन स्वास्थ्य सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को इसकी जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पात्र हितग्राहियों तक इनका लाभ समय पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वानखड़े ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं, उपलब्ध संसाधनों तथा उपचार संबंधी सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान उन्होंने स्वयं अपना ब्लड शुगर परीक्षण भी कराया तथा स्वास्थ्य जांच एवं नियमित परीक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कलेक्टर श्री वानखड़े ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि शासन द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी नागरिक आगे आकर इन सेवाओं का लाभ लें तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।



विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्वालियर ने दिया पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश

रमौआ जलाशय पर श्रमदान, आनंद पर्वत पर पौधरोपण और ई-वाहन रैली से जन-जन को किया जागरूक

ग्वालियर (निप्र)। विश्व

पर्यावरण दिवस पर ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में सरकार की मंशा के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों और आम नागरिकों ने मिलकर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन, ऊर्जा बचत और हरित विकास का प्रभावी संदेश जन-जन तक पहुंचाया।

रमौआ जलाशय पर श्रमदान से दिया जल संरक्षण का संदेश : दिन की शुरुआत रमौआ जलाशय पर व्यापक स्वच्छता अभियान से हुई। सुबह

6 बजे से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों नागरिकों ने श्रमदान कर जलाशय के घाटों और आसपास फैले कचरे को हटाया। लोगों ने दस्ताने पहनकर पूजन सामग्री, पॉलीथिन, कपड़े और अन्य अपशिष्ट एकत्रित किए। अभियान के दौरान 6 से 7 डंपर कचरा हटाय़ा गया। इस स्थानीय अभियान से प्रभावित होकर रचना-रचना ग्रामीण भी सफाई कार्य में शामिल हुए और भविष्य में जलाशय को स्वच्छ बनाए रखने तथा उसमें कचरा फेंकने वालों को रोकने का संकल्प लिया।

आनंद पर्वत पर पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने का लिया संकल्प : इसके बाद आनंद पर्वत पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर की बंजर पहाड़ियों को हरियाली से आच्छादित करने के संकल्प के साथ यहाँ प्रतीक स्वरूप 101 पौधे रोपे गए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव सहित अन्य अधिकारियों एवं नागरिकों ने पौधरोपण कर वर्षाकाल में होने वाले व्यापक वृक्षारोपण अभियान की सामूहिक तैयारी का संदेश दिया। साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

विदिशा के शिक्षक ने एक ही पेड़ पर आदि 35 तरह के आम! जापानी ‘मियाजाकी’ और 6 किलो वजन वाला ‘ब्लूनाई किंग’ भी लटक रहा

विदिशा (नप्र)। कहते हैं कि अगर कुछ नया सीखने की ललक और सही वैज्ञानिक सोच हो, तो मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। इसे सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पमारिया गांव के रहने वाले शिक्षक और प्रगतिशील किसान बालकृष्ण विश्वकर्मा ने। उन्होंने अपने अनूठे नवाचारों और कड़े परिश्रम से पारंपरिक खेती को आधुनिकता का ऐसा रंग दिया है कि आज वे पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़े रोल मॉडल और प्रेरक उदाहरण बन चुके हैं।

बगीचे में महक रहा है दुनिया का सबसे महंगा ‘मियाजाकी’ आम

शिक्षक बालकृष्ण विश्वकर्मा ने अपने बगीचे में जापान की बेहद प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्मों में शुमार ‘मियाजाकी’ को सफलतापूर्वक तैयार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये किलो तक बिकने वाले इस आम की एमपी के एक छोटे से गांव में सफल पैदावार होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।



ग्राफ्टिंग कर किया जादू, एक पेड़ पर 35 किस्में!

शिक्षक की वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण उनके द्वारा अपनाई गई ग्राफ्टिंग (कलमकारी) तकनीक है। इस तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल से उन्होंने एक ही आम के पेड़ पर 35 अलग-अलग किस्में विकसित कर दी हैं। यानी एक ही पेड़ की अलग-अलग टहनियों पर अलग-अलग स्वाद और प्रजातियों के आम फल रहे हैं, जो कृषि विशेषज्ञों के लिए भी कौतूहल का विषय है।

6 किलो का ‘ब्लूनाई किंग’ और ‘अंगूर दाना’ आम भी हैं मौजूद

शिक्षक बालकृष्ण का बगीचा इस समय दुर्लभ आमों का गढ़ बना हुआ है और दूर-दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। उनके बगीचे में जहां एक तरफ दुनिया का सबसे भारी माना जाने वाला ‘ब्लूनाई किंग’ आम आकर्षण का केंद्र है, जिसका वजन 6 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे छोटे आकार का ‘अंगूर दाना’ आम भी इसी बगीचे की शोभा बढ़ा रहा है।

स्कूटी सवार बदमाशों ने की हवाई फायरिंग

गाली-गलौज करते हुए कई राउंड फायर किए, भागते समय गिरी स्कूटी, सीसीटीवी आया सामने

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की अशोका कॉलोनी में शुक्रवार देर रात स्कूटी सवार दो बदमाशों ने सर्राह हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वारदात के बाद भागते समय बदमाशों की स्कूटी असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें पकड़ पाते उससे पहले ही दोनों मौके से फरार हो गए। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जो रविवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे दो युवक स्कूटी से अशोका कॉलोनी की एक गली में पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने वहां पहुंचकर गाली-गलौज शुरू कर दी और इसके बाद हवा में कई राउंड फायर कर दिए। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाश किसी को डराने या इलाके में अपना प्रभाव दिखाने के इरादे से पहुंचे थे। हालांकि फायरिंग का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

भागते समय गिरी स्कूटी

फायरिंग के बाद दोनों बदमाश तेजी से वहां से भागने लगे। इसी दौरान उनकी स्कूटी फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत स्कूटी उठाई और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। घटना की सूचना मिलते ही शाहजहानाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों युवकों की गतिविधियां कैद हुई हैं। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

गाड़ियों के शीशे टूटे, तीन पर एफआईआर शाजापुर में अवैध रेत खनन रोकने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर पथराव



शाजापुर (नप्र)। मध्य प्रदेश में रेत माफिया बेखोफ हैं। शाजापुर में कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम पर रेत माफियाओं ने पथराव किया है। इस हमले में कई सरकारी गाड़ी के कांच भी फूट गए हैं। इसके बाद रेत माफिया वहां से ट्रैक्टर लेकर भाग गए हैं।

जंगीखेड़ी गांव में हो रहा था खनन- दरअसल, कालापीपल क्षेत्र के जंगीखेड़ी गांव में खनिज विभाग के अधिकारियों पर पथराव हुआ। गांव में लंबे समय से अवैध खनन हो रही थी। मगर प्रशासन की टीम ने कभी यहां पहुंचकर कार्रवाई नहीं की है।

पार्वती नदी में अवैध खनन- बताया जा रहा है कि पार्वती नदी के किनारे अवैध उत्खन की शिकायत मिली थी। सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने टीम का विरोध किया और अचानक पत्थर फेंकने लगे। पत्थर शासकीय वाहन पर लगे, जिससे शीशे टूट गए। अधिकारी और कर्मचारी किसी तरह बच गए।

ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर फरार- हंगामे के बीच आरोपी ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर फरार हो

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कालापीपल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीन लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और नुकसान पहुंचाए की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। शुजालपुर एसडीओपी के अनुसार खनिज अमला वहां कार्रवाई करने पहुंची। ट्रैक्टर रोकने पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच जारी है।

इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर कार्रवाई करने गई टीम ही सुरक्षित नहीं है तो अवैध खनन पर कैसे रोक लगेगी। मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी रेत माफिया खनिज विभाग की टीम पर हमला करते रहे हैं।

गए। खनिज टीम ने मौके से रेत से भरा एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। लेकिन पत्थरबाजी की वजह से बाकी मशीनों को पकड़ने की कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है।

आंवले के बाद अब आम में बिखेरा जलवा

यह पहली बार नहीं है जब बालकृष्ण विश्वकर्मा ने ऐसा कोई कमाल किया हो। इससे पहले वे इलाके में आंवले की उन्नत खेती का सफल प्रयोग कर चुके हैं, जिससे प्रेरणा लेकर क्षेत्र के कई अन्य किसानों ने भी अपनी आमदनी को बढ़ाया था। उनकी यह लगातार सफलता दर्शाती है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयोग से कृषि क्षेत्र में कितने असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उनकी इस उपलब्धि की कहानी एमपी शासन व जिला प्रशासन भी बयां कर रहा है। जेडी जनसंपर्क सोशल मीडिया ने भी उनके फोटो शेयर किए हैं।

आजीविका नहीं, नवाचार की प्रयोगशाला

बता दें कि बालकृष्ण विश्वकर्मा जैसे शिक्षक सह किसान यह साबित करते हैं कि जब शिक्षा, आधुनिक सोच और कड़ी मेहनत का संगम होता है, तो खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया या आजीविका नहीं रह जाती, बल्कि वह नवाचार की एक जीवंत प्रयोगशाला बन जाती है। उनके ये प्रयास न केवल स्थानीय किसानों को पारंपरिक ढंग से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि भारतीय कृषि के भविष्य को भी एक नई और समृद्ध दिशा दे रहे हैं।

नरेला में बारिश पूर्व तैयारियों की जमीनी हकीकत जांचने निकले मंत्री सारंग

पातरा नाले में मिट्टी डंप होने पर जताई नाराजगी, तत्काल शुरू कराया मिट्टी हटाने का कार्य

भोपाल (नप्र)। आगामी मानसून को देखते हुए नरेला विधानसभा क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग रविवार सुबह स्वयं सड़कों पर उतरे और नरेला विधानसभा के प्रमुख नाले-नालियों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री श्री सारंग ने प्रभात चौराहा, महामाई की पुलिया, द्वारका नगर, भानपुर खंती सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति देखी और अधिकारियों को बरसात के पहले सफाई और मरम्मत करने के निर्देश दिए।

सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार- निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नाले-नालियों की सफाई कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मंत्री श्री सारंग ने नगरनिगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नाले-नालियों की पूरी तरह सफाई होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, आम



नागरिकों को बाढ़ जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जाए ताकि पानी की निकासी सुचारू बन सके।

पातरा नाले का किया विशेष निरीक्षण- दौरे के दौरान मंत्री श्री सारंग ने भोपाल शहर के सबसे बड़े पातरा नाले का भी निरीक्षण किया, जो नरेला विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पातरा नाला पूरे भोपाल शहर की जल निकासी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इसकी सफाई समय पर नहीं हुई तो बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो

सकती है। **एनएचआई के कार्य पर जताई नाराजगी-** भानपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने देखा कि एनएचआई द्वारा निर्माणाधीन 10 लेन प्रोजेक्ट के कार्य के चलते पातरा नाले में बड़ी मात्रा में मिट्टी डंप की गई है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाले में मिट्टी डंप होने से पानी का प्रवाह बाधित होगा और इसका असर पूरे भोपाल शहर पर पड़ेगा। बारिश के समय यह स्थिति बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इंदौर में यातायात नियमों की अनदेखी भारी, 5 महीने में 7 करोड़ का जुर्माना



इंदौर। शहर की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस लगातार कड़ा रुख अपना रही है। इस साल के शुरूआती पांच महीनों के भीतर ही पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूलने का आंकड़ा 7 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया। हालांकि, बीते चार महीनों के मुकाबले मई के महीने में पुलिस की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भीषण गर्मी और सोशल मीडिया पर उठती आवाजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों को थोड़ी राहत दी, जिसके कारण हेलमेट से जुड़े चालान आधे से भी कम रह गए। मई में पुलिस ने इस श्रेणी में केवल 12738 चालान ही बनाए। हेलमेट अभियान को थोड़ा धीमा करने के साथ ही यातायात पुलिस ने अपना पूरा ध्यान सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने वाले अन्य कारकों पर केंद्रित कर दिया।

मई महीने में गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों, दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने वालों, लाल बत्ती पार करने वालों, विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों और गाड़ी चलते समय दूरभाष पर बात करने वालों के खिलाफ विशेष कड़ाई बरती गई। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, तो मई 2026 में कुल 30928 वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे कुल 1 करोड़ 13 लाख 3 हजार 500 रुपए का शमन शुल्क एकत्रित हुआ। यह राशि अप्रैल 2026 के मुकाबले 58 लाख 86 हजार 750 रुपए कम रही, क्योंकि अप्रैल में पुलिस ने 47276 चालान काटकर रिकॉर्ड 1 करोड़ 71 लाख 90 हजार 250 रुपए का जुर्माना वसूला था।

यदि पिछले कुछ सालों के सरकारी खजाने में जमा हुए जुर्माने पर नजर डालें, तो साल 2023 में 070838400 रुपए, साल 2024 में 055710000 हजार रुपए और 2025 में 082888000 रुपए की वसूली की गई थी। वहीं इस साल 2026 में मई महीने तक ही यह राशि 072205200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस साल महीनेवार हुई कार्रवाई को देखें तो जनवरी में 41752 चालान से 1 करोड़ 50 लाख 87 हजार 800 रुपए, फरवरी में 40676 चालान से 1 करोड़ 37 लाख 64 हजार 900 रुपए, मार्च में 43921 चालान से 1 करोड़ 48 लाख 58 हजार 750 रुपए जमा किए गए, जो अप्रैल और मई की सख्त कार्रवाई के साथ बढ़ते हुए इस नए स्तर पर पहुंचे हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सुजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायतों के उप चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, उसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, फिर भी नगरीय निकाय के पांच अध्यक्षों के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने दो पर कब्जा जमा लिया। पार्षदों के 71 पदों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को 39 सीटें मिली। कांग्रेस के 30 पार्षद जीतकर आ गए। पंचायतों में गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए, लेकिन पंचायतों के नतीजों से कांग्रेस गदगद है। नगरीय निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में ही कांग्रेस पार्षद की जीत हो गई। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भले बीजेपी का अध्यक्ष चुनकर आ गया, पर बहुमत कांग्रेस पार्षदों का है। बताते हैं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के कई नेता और मंत्री लगे थे, इसके बाद भी बीजेपी को कलीन स्वीप न मिलना, सोचनीय है। राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार

को ढ़ाई साल हो गए हैं। 2023 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और नगरीय निकाय और जिला पंचायतों-जनपदों में भी दबदबा बनाया। राज्य के करीब-करीब सभी शहरी निकायों और पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आमतौर पर उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी की ही जीत होती है। लोग सत्ता की विपरीत धारा में बहते नजर नहीं आते, पर नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की नब्ब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे गांव-गांव पहुंचकर लोगों के दुख -दर्द के सहभागी बन रहे हैं, पर नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे जिस तरह आए हैं, उससे लग रहा है कि सरकार को काम करने का तौर-तरीका बदलना होगा और लोगों की समस्याओं के इलाज के लिए जल्दी ही कदम उठाना पड़ेगा।

पवन साय का बड़ेगा कद

छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन महामंत्री पवन साय के प्रमोशन की चर्चा है। कहते हैं कि पवन साय को जल्द ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाकर कम से कम दो राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कहा जा रहा है कि

पश्चिम बंगाल चुनाव में पवन साय के प्रभार वाले इलाके में बीजेपी का परफार्मेंस काफी अच्छा रहा। इसका पुरस्कार पवन साय को मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पवन साय के संगठन महामंत्री के कार्यकाल में 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य में सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भी बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। संगठन महामंत्री के तौर पर पवन साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, इस कारण उनका कद बढ़ना तय माना जा रहा है।

मंत्री जी की चंदा उगाही चर्चा में

राज्य के एक मंत्री जी की चंदा उगाही आज कल सुर्खियों में है। कहते हैं मंत्री जी ने अपने बच्चे की शादी की तो अपने विभाग के अफसरों को टारगेट दे दिया, फिर अपने इलाके में एक धार्मिक आयोजन करवाया तो फिर लक्ष्य दे दिया। बताते हैं कि धार्मिक आयोजन के लिए विभाग के जिला अधिकारियों को 10-10 लाख तक धन की व्यवस्था का फरमान दिया था। जिला

अधिकारियों ने अपना सिर दर्द मातहत अफसरों पर डाल दिया। इन मंत्री जी के बारे में चर्चा है कि वे 40 फीसदी तक कमीशन लिए बिना कोई विभागीय टेंडर और अन्य काम की मंजूरी नहीं देते। मंत्री जी के कमीशन प्रेम से विभाग का भट्टा बैठा जा रहा है और जनता परेशान है। वैसे जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल का हल्ला शुरू होता है, हटाए जाने वालों में इन मंत्री जी का नाम उसमें शामिल रहता है।

मजबूत पकड़ वाले कलेक्टर साहब

कहते हैं कि राज्य के एक कलेक्टर साहब से एक सांसद और एक विधायक भारी नाराज हैं और कलेक्टर को हटाने के लिए सांसद और विधायक जी पूरा जोर भी लगा रहे हैं, पर कलेक्टर साहब हैं कि अंगद के पांव की तरह जमे हैं। खबर है कि कलेक्टर साहब सांसद और विधायक जी की बैठकों में भाग नहीं लेते, वे अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। बैठकों में कलेक्टर साहब को गैरहाजिर पाकर सांसद और विधायक जी अपना भड़स निकालते हैं। बताते हैं कलेक्टर को हटवाने के लिए सांसद और विधायक जी ने भाजपा संगठन से एग्रेसिव किया है, पर अब तक बात बनी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कलेक्टर साहब को राज्य के एक मंत्री जी का

आशीर्वाद प्राप्त है। हल्ला है कि कलेक्टर साहब का राजनीतिक आधार काफी मजबूत है। इस कारण सांसद और विधायक महोदय की नाराजगी के बावजूद कलेक्टर साहब बड़े जिले में राज कर रहे हैं।

प्रशासनिक फेरबदल से खफा मंत्री

कहते हैं पिछले महीने हुए व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से राज्य के कुछ मंत्री खफा हैं और मुख्यमंत्री के सामने आपत्ति भी दर्ज करवा चुके हैं। बताते हैं प्रशासनिक फेरबदल करने से पहले मंत्रियों से न तो पूछा गया और न ही उनकी राय ली गई। खबर है कि कुछ अफसरों ने लिस्ट बनाई और मुख्यमंत्री से मंजूरी ले ली। बताते हैं कि कुछ मंत्रियों के विभागों में ऐसे अफसरों की पोस्टिंग कर दी है, जिन्हें वे पसंद नहीं करते। अब मंत्री और अफसरों में टकराव शुरू हो गया है। एक मंत्री के पसंदीदा सचिव को उनके विभाग से हटा दिया गया। इससे मंत्री बड़े नाराज बताए जाते हैं। एक मंत्री की अपने विभागाध्यक्ष से बढ़िया तालमेल बैठ गया था। अब उस विभाग में ऐसे अफसर को सचिव के तौर पर पदस्थ कर दिया गया है, जो विभागाध्यक्ष पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। इससे मंत्री जी का काम अटक सा गया है। इससे मंत्री जी बड़े दुखी बताए जाते हैं।

